



परंपरा और तकनीक का नवाचार वस्त्र प्रद्यौगिकी में सपनों का द्वार

उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नालॉजी इंस्टीट्यूट

111 वर्षों की गौरवशाली विरासत ■ भविष्य के लीडर्स की पाठशाला ■ यहां युवा बुनते हैं इनोवेशन और बनते हैं पेशेवर

मैं नचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहे जाने वाले कानपुर में स्थित “उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नालॉजी इंस्टीट्यूट (यूपीटीटीआई)” उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि देश के सबसे पुराने और अग्रणी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है। 1914 में स्थापित इस संस्थान ने बीते 111 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में हजारों युवाओं को तकनीकी शिक्षा, रिसर्च और उद्योगोन्मुख प्रशिक्षण से सशक्त बनाकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के विकास को नई राह दिखाई है। यह संस्थान देश को तकनीकी रूप से दक्ष और उद्योग के अनुकूल प्रोफेशनल्स उपलब्ध करा रहा है।



ऑटोमोटिव और मेडिकल सेक्टर में टेक्सटाइल इंजीनियर्स की बढ़ी मांग

■ तेजी से बदलती दुनिया के दौर में आज लगभग सभी क्षेत्रों में टेक्सटाइल इंजीनियर्स की जरूरत है। खासतौर पर ऑटोमोटिव और मेडिकल सेक्टर में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की जरूरत पिछले कुछ समय में तेजी से महसूस की जा रही है। कंप्यूटर साइंस व टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के छात्र एक साथ मिलकर इस आवश्यकता को नई दिशा दे सकते हैं।

इसे ही भांपकर यूपीटीटीआई ने टेक्सटाइल से जुड़े पाठ्यक्रमों टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, मैन मेड फाइबर टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अलावा सत्र 2024-25 से कंप्यूटर साइंस में 60 सीटों वाला बीटेक कोर्स शुरू किया है। इसके पीछे संस्थान का प्रयास है कि छात्र सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि उद्योग के निर्माण और नेतृत्व के लिए भी तैयार हो सकें।

देश में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री

■ टेक्सटाइल इंडस्ट्री करियर के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग है। इसमें नौकरी, रिसर्च, फैशन डिजाइन, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट, टेक्निकल टेक्सटाइल, क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाय चेन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट सेक्टर, स्टार्टअप्स, इनोवेशन, एनवायरमेंटल टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र में काम करने के लिए राष्‍ट्रीय और बहुराष्‍ट्रीय कंपनियों में अपार अवसर उपलब्ध हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में इनोवेशन और रिसर्च की भी असीम संभावनाएं हैं।

संस्थान में उपलब्ध पाठ्यक्रम

- बीटेक – कम्प्यूटर साइंस – 60 सीटें, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी – 40 सीटें, टेक्सटाइल केमिस्ट्री – 60 सीटें, मैन मेड फाइबर टेक्नोलॉजी – 60 सीटें, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग – 40 सीटें (प्रवेश प्रक्रिया जेईई मेंस, सीयूईटी तथा यूपीटेक)
- एमटेक – टेक्सटाइल टेक्नालॉजी, टेक्सटाइल केमिस्ट्री (प्रवेश प्रक्रिया गेट तथा सीयूईटी (पीजी) उत्तीर्ण, सीटें रिक्त रहने पर संस्थान स्तरीय प्रवेशपरीक्षा)
- पीएचडी – रिसर्च व इनोवेशन

लेखक – प्रोफेसर जितेन्द्र प्रताप सिंह
हेड ऑफ डिपार्टमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट
उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नालॉजी इंस्टीट्यूट

शत प्रतिशत प्लेसमेंट, उद्योग जगत के लीडर

■ यूपीटीटीआई ने हाल के वर्षों में लगभग शत प्रतिशत प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया है। संस्थान के छात्रों की मांग टेक्सटाइल उद्योग में हमेशा रहती है। यहां के छात्रों को देश की शीर्ष टेक्सटाइल कंपनियों में आकर्षक पैकेज पर नौकरी मिली है। यूपीटीटीआई के छात्र देश-विदेश की नामी टेक्सटाइल कंपनियों जैसे ट्राइडेंट ग्रुप, वेलस्पन, वर्धमान टेक्सटाइल्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आदित्य बिड़ला ग्रुप, शाही एक्सपोर्ट्स, नाहर ग्रुप आदि में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। संस्थान के अनेक पूर्व छात्रों ने टेक्सटाइल सेक्टर में अपना स्टार्टअप भी शुरू करके नए आयाम स्थापित किए हैं।

■ संस्थान की आधुनिक लेब्स में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मशीनरी और उपकरण हैं, जिससे छात्रों को वास्तविक इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है। टेक्नोलॉजी-सक्षम क्लासरूम और समृद्ध लाइब्रेरी में छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज और रिसर्च के लिए हर सुविधा उपलब्ध रहती है।

नवाचार को नई उड़ान, संस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान

■ संस्थान का स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर एंड इनोवेशन फाउंडेशन संस्थान के छात्रों के साथ ही बाहरी युवाओं के लिए नवाचार के सशक्त केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसे प्रदेश सरकार के स्टार्ट इन यूपी और एकेटीयू के इनोवेशन हब से मान्यता मिली हुई है।

■ सेंटर युवा उद्यमियों को उनकी स्टार्टअप यात्रा में आइडिया से स्टार्टअप तक की मेंटरशिप, सरकारी ग्रांट्स और स्क्रीम्स की जानकारी, लीगल व अकाउंटिंग सहायता, बिजनेस प्लान डेवलपमेंट, फंडिंग और नेटवर्किंग सपोर्ट में सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके चलते संस्थान के नवाचारों को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, इंटरनेशनल ट्रेड शो, स्टार्ट अप महाकुंभ-2024 एवं 25 तथा स्टार्ट अप संवाद जैसे आयोजनों में सराहना हासिल हुई है।

जॉब अलर्ट

एलआईसी रिक्रूटमेंट-2025

- असिस्टेंट इंजीनियर – 81 पद
- असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर – 760 पद
- अहर्ता – मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री, बीई/ बीटेक और लॉ में ग्रेजुएट
- आयु सीमा – 8 सितंबर 2025 को कम से कम 21 साल और अधिकतम 30/32 साल
- आवेदन – ऑनलाइन www.licindia.in
- अंतिम तिथि – 8 सितंबर

यूपी पुलिस दरोगा भर्ती

- कुल पद – 4543
- योग्यता – स्नातक
- आवेदन – वेबसाइट Uppbpb.gov.in
- अंतिम तिथि – 11 सितंबर

बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति

- कुल पद – 1064
- योग्यता – स्नातक
- आयु सीमा – 21 से 37 वर्ष
- आवेदन – वेबसाइट Bssv.bihar.gov.in
- अंतिम तिथि – 17 सितंबर

काम की बात

स्वयं पोर्टल पर पांच फ्री एआई कोर्स लॉन्च

■ शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने के लिए स्वयं पोर्टल पर पांच फ्री एआई कोर्स लॉन्च किए हैं। स्कूल-कॉलेज के छात्र और नौकरीपेशा, सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन कोर्स को आईआईटी के प्रोफेसरों ने डिजाइन किया है। ये कोर्स बैसिक से एडवांस लेवल तक की घर बैठे पढ़ाई के लिए तैयार किए गए हैं। कोर्स पूरा करने पर छात्रों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

‘AI/ML Using Python’ कोर्स में पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा विजुअलाइजेशन और मशीन लर्निंग की बैसिक जानकारी दी जाएगी।

‘AI in Physics’ कोर्स में फिजिक्स के कठिन कॉन्सेप्ट्स को AI की मदद से आसान तरीके से समझाया जाएगा। इसी तरह ‘AI in Chemistry’ कोर्स में इग डिजाइनिंग और रिफ्रक्शन मॉडलिंग जैसे विषयों को AI के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा। कोर्स और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए ‘AI in Accounting’ कोर्स में अकाउंटिंग ऑटोमेशन और स्मार्ट एनालिसिस सिखाया जाएगा। इन कोर्स के लिए [SWAYAM पोर्टल swayam.gov.in](http://SWAYAM.gov.in) पर लॉग इन करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं देना है।

सैन्य कॉलेज देहरादून में एडमिशन

■ राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, देहरादून में जुलाई 2026 सत्र के लिए 8वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7वीं कक्षा में पढ़ रहे या 7वीं पास कर चुके लड़के या लड़कियां इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

■ उम्र 1 जुलाई 2026 को साढ़े ग्यारह साल से कम और 13 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रवेश परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को दिल्ली में होगी।

■ आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। प्रवेश परीक्षा दो स्तरीय होगी। लिखित परीक्षा अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान की होगी। इसे पास करने वाले बच्चों का बाद में साक्षात्कार होगा।

■ आवेदन फार्म डिमांड ड्राफ्ट भेजकर कॉलेज से मंगा सकते हैं या शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

■ राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, देहरादून बच्चों को पढ़ाई के साथ अनुशासन, फिजिकल ट्रेनिंग और लीडरशिप सिखाता है। यहां कक्षा 8 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है।

■ इस कॉलेज को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), देहरादून के लिए नर्सरी ऑफ लीडरशिप माना जाता है।

■ यहां से पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों के लिए सेना में अधिकारी बनने का रास्ता खुलता है।

अंग्रेजी में कमजोरी नहीं बनेगी उच्च शिक्षा में बाधा

अंग्रेजी भाषा में कमजोर होने के कारण तमाम मेधावी छात्र-छात्राओं को एमबीबीएस, बीटेक या प्रबंधन की पढ़ाई में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम और उससे संबंधित विशिष्ट महत्वपूर्ण पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए सरकार ‘भारतीय भाषा पुस्तक’ योजना को तेजी से धरातल पर लाने में जुटी है। यह कदम उन छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद होगा, जो हिंदी मीडियम या अपने राज्य की भाषा से शुरूआती पढ़ाई करते हैं और अंग्रेजी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इस काम के लिए शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने देश की प्रमुख यूनिवर्सिटीज व उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज की मैपिंग पूरी कर ली है। राज्यों की भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के मिशन में वहां की यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

देश में हर भाषा में मिलेगी कोर्स की किताबें

- कोर्स से जुड़ी पांच हजार किताबें भारतीय भाषाओं में होगी तैयार
- 22 भारतीय भाषाओं में मिलेगी इंजीनियरिंग-मेडिकल की किताबें
- जेईई 13 क्षेत्रीय भाषाओं में



हिंदी में भी शुरू मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई

- कई प्रमुख संस्थानों ने हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू भी कर रखी है, मध्य प्रदेश, बिहार, और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। आईआईटी, जोधपुर बीटेक कोर्स को हिंदी भाषा में उपलब्ध करा चुका है।
- छात्रों को डिजिटल प्रारूप में टेक्स्टबुक और अध्ययन सामग्री मिलेगी।
- क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और भाषा आधारित समानता सुनिश्चित होगी।
- तकनीकी, मेडिकल, लॉ और अन्य उच्च शिक्षा की किताबों का अनुवाद किया जाएगा।

पहली प्राइवेट नौकरी पर सरकार से 15 हजार इनाम

- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना
 - खुल चुका पोर्टल, इस तरह करना है रजिस्ट्रेशन
- देश में युवाओं को अधिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने Employment Linked Incentive Scheme शुरू की है। इस योजना को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी मिलने पर सरकार धन देगी।
- प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले लोगों को इस योजना का लाभ लेने के लिए UAN (Universal Account Number) फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए UMANG App पर जेनरेट करना होगा। वहीं, एंप्लॉयर pmvbry.epfindia.gov.in या pmvbry.labour.gov.in पर जाकर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच बनने वाली नौकरियों पर लागू होगी।
- योजना का पोर्टल (<https://pmvbry.epfindia.gov.in> या <https://pmvbry.labour.gov.in>)



योजना का पहला भाग

इस योजना में दो पार्ट हैं। पार्ट ए पहली बार रोजगार पाने वालों पर केंद्रित है, वहीं दूसरा भाग नियोक्ताओं पर केंद्रित है। पार्ट ए के तहत EPFO में पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को एक महीने का EPF वेतन, जो अधिकतम 15000 रुपये हो सकता है, दो किस्तों में दिया जाएगा। 6 महीने की नौकरी पूरी होने पर 7500 रुपये और बाकी 7500 रुपये 1 साल पूरा होने पर मिलेंगे। 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत साधन या जमा खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी बाद में इसे निकाल सकेगा।

दूसरा भाग नियोक्ताओं के लिए

नियोक्ताओं को हर अतिरिक्त कर्मचारी (पहली बार नौकरी करने वाला या पुनः जुड़ने वाला) पर रुपये 3000 प्रति माह तक का Incentive मिलेगा। यह प्रोत्साहन सामान्य तौर पर 2 साल तक और मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में 4 साल तक रियाज जाएगा।

लाभ तभी मिलेगा जब कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक नौकरी में बना रहे।

पात्रता की शर्तें

- जिन प्रतिष्ठानों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे।
- जिनमें 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे।
- Exempted Establishments भी इस योजना के तहत शामिल होंगे और उन्हें अपने सभी कर्मचारियों का UAN खोलना अनिवार्य होगा।